

1	2	3	4	5	6
4.	Tawa left Bank Canal	Jan.83	4×3	13.51	The third revised report has been received in CEA in Sept.83. The report is in advanced stage of examination and is likely to be put up to CEA for techno-economic clearance in the next meeting.
5.	Mahan HE Project.	Jan.83	0.5	0.55	Since the total cost of the scheme is less than Rs.1.00 crore, the project authorities have been informed that there is no requirement of clearance of the scheme by CEA and the same could be taken up for execution by the M.P. Electricity Board under its own power.

Non-Availability of Drugs in Maharashtra

3300. DR. PRATAP WAGH : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to non-availability of essential drugs such as Syntocinon, methergin, cardioxin, hydergine and malleril in Bombay and other places in Maharashtra ; and

(b) the steps proposed by Government to improve the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI R.C. RATH): (a) and (b) Localised shortage of Syntocinon and Methergin injections was reported from some areas in Maharashtra. However, equivalent drug formulations Pitocin Injection (Parke Davis) and Neogynergen injection (Sandoz) are reportedly available.

There is no reported shortage of Cardioxin, Hydergine and Melleril.

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3301. श्री मूलचन्द्र डागा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में श्रम

ब्यूरो को असंगठित क्षेत्रों के विभिन्न उद्योगों का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था, और यदि हां तो कब ; और

(ख) असंगठित क्षेत्र के उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया तथा दिल्ली में भवन तथा निर्माण उद्योग के बारे में उसके क्या निष्कर्ष थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी हां। जिन उद्योगों में श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण किए गए हैं, उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। ऐसी रिपोर्टों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का कार्य है।

विवरण

असंगठित क्षेत्र के जिन उद्योगों के, जिनमें श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण किए गए हैं, नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. दिल्ली में भवन तथा निर्माण उद्योग (1977-78)
2. सिवाकासी में तथा उसके आस-पास आतिशबाजी उद्योग (1979)